E-ISSN: 2664-603X
P-ISSN: 2664-6021
IJPSG 2025; 7(12): 119-127
www.journalofpoliticalscience.com
Received: 25-09-2025
Accepted: 30-10-2025

Jagesh Kumar
Research Scholler, Department of Political Science, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, Himachal Pradesh, India

Jagmeet Singh Bawa
Professor, Department of South and Central Asian Studies School of International Studies, Central University of Punjab, Bathinda, Punjab, India

Corresponding Author:
Jagesh Kumar
Research Scholler, Department of Political Science, Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala, Himachal Pradesh, India

नई विश्व व्यवस्था में भारत–उज़्बेकिस्तान रणनीतिक सहयोग: अवसर, चुनौतियाँ और संभावनाएँ

Jagesh Kumar and Jagmeet Singh Bawa

DOI: https://www.doi.org/10.33545/26646021.2025.v7.i12b.781

सारांश
इक्कीसवीं सदी के तीसरे दशक में विश्व राजनीति तीव्र गति से बहुध्रुवीयता की ओर बढ़ती दिखाई देती है। अमेरिका, चीन, रूस, यूरोपीय संघ, भारत और अन्य उभरती शक्तियाँ मिलकर ऐसी अंतरराष्ट्रीय संरचना का निर्माण कर रही हैं, जिसे नई विश्व व्यवस्था के रूप में समझा जा सकता है। इस व्यवस्था में एशिया, विशेषकर दक्षिण और मध्य एशिया, ऊर्जा–सुरक्षा, संपर्क–कॉरिडोर, व्यापार–मार्गों और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के केंद्र के रूप में उभर रहे हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान, दोनों, इस बदलती परिस्थिति में अपनी विदेश नीति और रणनीतिक प्राथमिकताओं को नए सिरे से परिभाषित कर रहे हैं। भारत बहुध्रुवीय विश्व और बहुध्रुवीय एशिया की अवधारणा को सुदृढ़ करने के लिए बहु–संसक्ति या मल्टी–अलाइनमेंट की रणनीति पर चल रहा है, वहीं उज़्बेकिस्तान बहु–दिशात्मक या मल्टी–वेक्टर विदेश नीति तथा "लैण्डलॉक्ड से लैण्डलिंक्ड" बनने की दीर्घकालिक दृष्टि के साथ आगे बढ़ रहा है (Baghdasaryan, 2024)। इस संदर्भ में दोनों देशों के बीच 2011 में स्थापित रणनीतिक साझेदारी ने राजनीतिक, सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक, ऊर्जा, संपर्क, शिक्षा और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर खोले हैं। हाल के वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार, रक्षा–सुरक्षा सहयोग, संपर्क–पहल, शिक्षा–संस्कृति आदान–प्रदान और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, किंतु यह सहयोग अभी भी अपनी संपूर्ण संभावनाओं तक नहीं पहुँच पाया है। लॉजिस्टिक बाधाएँ, अफगानिस्तान की अस्थिरता, ईरान से जुड़ी अनिश्चितताएँ, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और संस्थागत सीमाएँ इसके प्रमुख अवरोधक हैं। यह शोध–पत्र नई विश्व व्यवस्था के सैद्धांतिक संदर्भ में भारत–उज़्बेकिस्तान रणनीतिक सहयोग का विश्लेषण करता है। प्रारंभ में बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था, भारत की मल्टी–अलाइनमेंट रणनीति और उज़्बेकिस्तान की मल्टी–वेक्टर नीति पर चर्चा की गई है। इसके बाद भारत–उज़्बेकिस्तान संबंधों के ऐतिहासिक–सांस्कृतिक तथा संस्थागत विकास की समीक्षा की गई है। तीसरे भाग में वर्तमान सहयोग के प्रमुख आयामों – राजनीतिक, सुरक्षा–रक्षा, आर्थिक–व्यापारिक, संपर्क–कॉरिडोर, ऊर्जा तथा शिक्षा–संस्कृति – का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। चौथे भाग में इस सहयोग के अवसरों और चुनौतियों का मूल्यांकन किया गया है और अंततः निष्कर्ष भाग में भविष्य की संभावनाओं के साथ कुछ नीतिगत सुझाव दिए गए हैं।

कुटशब्दः नई विश्व व्यवस्था, भारत–उज़्बेकिस्तान सहयोग, बहुध्रुवीयता, मल्टी–अलाइनमेंट, संपर्क–कॉरिडोर, रणनीतिक साझेदारी

1. प्रस्तावना

1.1 शोध–समस्या की पृष्ठभूमि

शीत युद्ध की समाप्ति ने अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में एक नई स्थिति उत्पन्न की। प्रारंभिक चरण में लगता था कि एकध्रुवीय अमेरिकी वर्चस्व लंबे समय तक बना रहेगा, लेकिन वैश्विक आर्थिक शक्ति–केंद्रों के विस्तार, क्षेत्रीय संगठनों के उदय और उभरती अर्थव्यवस्थाओं के सशक्त होने के साथ ही विश्व राजनीति बहुध्रुवीय स्वरूप ग्रहण करने लगी। तीसरे दशक में यह प्रक्रिया और तेज हो गई है।

रूस–यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम–चीन प्रतिद्वंद्विता, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, ऊर्जा–आपूर्ति में उतार–चढ़ाव, वैश्विक आपूर्ति–श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, जलवायु–संकट और तकनीकी प्रतिस्पर्धा ने नई विश्व व्यवस्था की बहस को केंद्र में ला दिया है। इन परिस्थितियों में न केवल शक्तिसंतुलन बदल रहा है, बल्कि क्षेत्रीय और मध्य–स्तरीय शक्तियों के लिए भी नए अवसर और चुनौतियाँ पैदा हो रही हैं (Baghdasaryan, 2024)।

इसी संदर्भ में दक्षिण और मध्य एशिया की रणनीतिक प्रासंगिकता बढ़ती जा रही है। मध्य एशिया के देशों, विशेषकर उज़्बेकिस्तान, की ऊर्जा–संपदा, भू–स्थानिक स्थिति, खनिज संसाधन और संपर्क–कॉरिडोर की संभावनाएँ उन्हें वैश्विक और क्षेत्रीय शक्तियों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाती हैं। दूसरी ओर भारत दक्षिण एशिया की प्रमुख शक्ति होने के साथ–साथ हिंद–प्रशांत, पश्चिम एशिया और यूरेशिया तक फैले व्यापक रणनीतिक परिदृश्य में एक महत्त्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में उभरा है।

इन दोनों क्षेत्रों – दक्षिण एशिया और मध्य एशिया – के बीच ऐतिहासिक–सांस्कृतिक, व्यापारिक और आध्यात्मिक जुड़ाव प्राचीन काल से रहा है। किंतु औपनिवेशिक युग, शीत युद्ध की खेमाबंदी और सोवियत नियंत्रण ने इन संपर्क–मार्गों को काफी हद तक सीमित कर दिया था। सोवियत संघ के विघटन और मध्य एशियाई गणराज्यों की स्वतंत्रता के बाद ही भारत को इस क्षेत्र के साथ अपने पुराने रिश्तों को पुनर्जीवित करने का अवसर मिला।

आज जब नई विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय स्वरूप ले रही है, भारत–उज़्बेकिस्तान संबंध केवल द्विपक्षीय स्तर पर नहीं, बल्कि व्यापक भू–राजनीतिक और भू–आर्थिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो गए हैं।

1.2 शोध–प्रश्न

इस शोध–पत्र का मुख्य प्रश्न यह है कि नई विश्व व्यवस्था में भारत–उज़्बेकिस्तान रणनीतिक सहयोग किन अवसरों और चुनौतियों के बीच विकसित हो रहा है और भविष्य में इसकी क्या संभावनाएँ हैं।

इस मुख्य प्रश्न के अंतर्गत कुछ उप–प्रश्न स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। पहला, बहुध्रुवीय नई विश्व व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएँ क्या हैं और भारत तथा उज़्बेकिस्तान की विदेश नीतियों को वे किस प्रकार प्रभावित कर रही हैं। दूसरा, भारत–उज़्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख आयाम कौन–कौन से हैं और वे कितनी हद तक परस्पर पूरक हैं। तीसरा, इस सहयोग के सामने कौन–कौन सी संरचनात्मक, भू–राजनीतिक और संस्थागत चुनौतियाँ हैं। चौथा, भविष्य में इस साझेदारी को और अधिक गहरा और संस्थागत बनाने के लिए कौन–से नीतिगत कदम उठाए जा सकते हैं (Barari and Mozaffari Falarti, 2023)।

1.3 शोध–कार्यप्रणाली

यह अध्ययन मुख्यतः गुणात्मक और विश्लेषणात्मक प्रकृति का है। इसमें सरकारी नीति–दस्तावेज़ों, आधिकारिक वक्तव्यों, विद्वत्तापूर्ण लेखों, थिंक–टैंक रिपोर्टों और मीडिया–विश्लेषणों जैसे द्वितीयक स्रोतों पर आधारित व्याख्यात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

सैद्धांतिक स्तर पर बहुध्रुवीयता, जटिल परस्पर–निर्भरता और क्षेत्रीयतावाद जैसी अवधारणाओं को विश्लेषण के औज़ार के रूप में उपयोग किया गया है। इन सिद्धांतों के विस्तृत सैद्धांतिक वाद–विवाद में गए बिना, उन्हें केवल इस बात को समझने के लिए प्रयुक्त किया गया है कि उभरती विश्व व्यवस्था में भारत और उज़्बेकिस्तान जैसे मध्यम आकार की शक्तियाँ किस प्रकार अपनी भूमिका निर्धारित करती हैं।

2. नई विश्व व्यवस्था: बहुध्रुवीयता, मल्टी–अलाइनमेंट और मल्टी–वेक्टर नीति

2.1 बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का उदय

शीत युद्ध के दौर में विश्व व्यवस्था मोटे तौर पर दो महाशक्ति–केंद्रों – अमेरिका और सोवियत संघ – के इर्द–गिर्द संगठित थी। सोवियत संघ के विघटन के पश्चात कुछ समय के लिए ऐसा प्रतीत हुआ कि अमेरिका का एकध्रुवीय वर्चस्व स्थिर रहेगा। किंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था के संतुलन में बदलाव, चीन और अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तीव्र वृद्धि, रूस की पुनर्सक्रियता, यूरोपीय संघ का सामूहिक प्रभाव, तथा विभिन्न क्षेत्रीय संगठनों के सशक्त होने से शक्ति–संतुलन धीरे–धीरे बहुध्रुवीय हो गया।

आज की नई विश्व व्यवस्था में कोई भी एक शक्ति अकेले वैश्विक एजेंडा निर्धारित नहीं कर सकती। बड़े मुद्दों पर शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा और सहयोग दोनों समानांतर रूप से मौजूद हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका और चीन के बीच सामरिक प्रतिद्वंद्विता स्पष्ट है, लेकिन दोनों के बीच आर्थिक परस्पर–निर्भरता भी अत्यंत गहरी है। रूस और पश्चिम के बीच तनाव के बावजूद ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग के उदाहरण भी मिलते हैं। यह बहुध्रुवीयता क्षेत्रीय शक्तियों जैसे भारत, तुर्की, ईरान, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका और मध्य एशियाई देशों के लिए अवसर और चुनौती दोनों लेकर आई है। इन देशों को अब अपने हितों की अधिक सक्रिय रूप से व्याख्या और रक्षा करनी पड़ती है, साथ ही वे विभिन्न शक्ति–केंद्रों के साथ संतुलित संबंध बनाने की कोशिश करते हैं।

2.2 भारत की "मल्टी–अलाइनमेंट" रणनीति और बहुध्रुवीय एशिया

भारत ने शीत युद्ध के दौर में गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाई थी। समय के साथ यह स्पष्ट हुआ कि नई वैश्विक परिस्थिति में केवल "दूरी बनाए रखने" की नीति पर्याप्त नहीं है। इसलिए भारत ने

धीरे–धीरे "मल्टी–अलाइनमेंट" या बहु–संसक्ति की रणनीति विकसित की, जिसमें वह अलग–अलग मुद्दों पर विभिन्न साझेदारों के साथ सहयोग करता है, लेकिन किसी एक खेमे में पूर्ण रूप से शामिल नहीं होता।

आज भारत सुरक्षा के क्षेत्र में क्वाड जैसे समूहों में सक्रिय है, वहीं आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिक्स, शंघाई सहयोग संगठन और अन्य मंचों में भी प्रमुख भूमिका निभा रहा है। भारत की विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण लक्ष्य बहुध्रुवीय विश्व के साथ–साथ बहुध्रुवीय एशिया को भी बढ़ावा देना है, ताकि एशिया में किसी एक शक्ति, विशेषकर चीन, का सर्वाधिक प्रभुत्व न स्थापित हो जाए (Bukhari, 2025)।

इंडो–पैसिफिक से लेकर यूरेशिया तक फैले भू–क्षेत्र में भारत स्वयं को एक ऐसे "सेतु–राज्य" के रूप में प्रस्तुत करता है, जो पश्चिमी लोकतांत्रिक शक्तियों, ग्लोबल साउथ और यूरेशियन क्षेत्र के बीच पुल का काम कर सकता है। इसी व्यापक दृष्टि में मध्य एशिया और विशेष रूप से उज़्बेकिस्तान के साथ घनिष्ठ संबंधों की महत्ता निहित है।

2.3 उज़्बेकिस्तान की "मल्टी–वेक्टर" विदेश नीति

उज़्बेकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही बहु–दिशात्मक या मल्टी–वेक्टर विदेश नीति की घोषणा की। इस नीति का मूल उद्देश्य यह है कि देश किसी एक शक्ति या समूह पर पूर्ण निर्भरता के बजाय अलग–अलग शक्तिकेंद्रों के साथ संतुलित संबंध बनाए रखे। राष्ट्रपति शवकत मिर्ज़ियोयेव के नेतृत्व में उज़्बेकिस्तान ने आंतरिक सुधारों के साथ–साथ क्षेत्रीय सहयोग को भी प्राथमिकता दी है। पड़ोसी मध्य एशियाई देशों के साथ सीमा–समझौतों, जल–संसाधन, व्यापार और संपर्क के मुद्दों पर नई पहलें की गई हैं। उज़्बेकिस्तान रूस, चीन, यूरोपीय संघ, तुर्की, पश्चिम एशिया और दक्षिण एशिया, विशेषकर भारत, सभी के साथ संतुलित संबंध विकसित करने की कोशिश कर रहा है।

इस नीति का एक महत्वपूर्ण घटक "लैण्डलॉक्ड से लैण्डलिंक्ड" बनने की दीर्घकालिक रणनीति है। उज़्बेकिस्तान अपने भू–अवरोधित होने की स्थिति को एक अवसर में बदलना चाहता है, जिसके लिए वह विभिन्न स्थलीय और समुद्री संपर्क–कॉरिडोरों से जुड़ने की योजना बना रहा है। चीन–किर्गिस्तान–उज़्बेकिस्तान रेल–मार्ग, कज़ाखस्तान–रूस–यूरोप कॉरिडोर, ईरान के बंदरगाहों के माध्यम से समुद्र तक पहुँच, और संभावित ट्रांस–अफगान कॉरिडोर इस दिशा में महत्वपूर्ण पहलें हैं। इस बहु–दिशात्मक नीति के अंतर्गत उज़्बेकिस्तान भारत के साथ गहरे संबंधों को एक ऐसी रणनीतिक संभावना के रूप में देखता है जो उसे चीन और रूस पर अत्यधिक निर्भरता से बचाते हुए विकल्पों का विविधीकरण प्रदान करती है।

3. भारत–उज़्बेकिस्तान संबंध: ऐतिहासिक और संस्थागत परिप्रेक्ष्य

3.1 ऐतिहासिक–सांस्कृतिक परंपरा

भारत और उज़्बेकिस्तान (या व्यापक रूप से मध्य एशिया) के बीच संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। सिल्क रूट के ज़रिए भारत, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया और यूरोप के बीच व्यापारिक और सांस्कृतिक नेटवर्क विकसित हुए। समरकंद, बुख़ारा और ताशकंद जैसे शहर सदियों तक व्यापार, विद्वा–परंपरा, इस्लामी अध्ययन, सूफी विचार और सांस्कृतिक संवाद के प्रमुख केंद्र रहे। भारतीय मसाले, वस्त्र, कीमती पत्थर और शिल्प–उत्पाद मध्य एशिया के बाज़ारों तक पहुँचते थे, जबकि मध्य एशिया से घोड़े, फर, रेशम, धातु और धार्मिक–दार्शनिक विचार भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करते थे। इस मार्ग ने न केवल व्यापारिक, बल्कि आध्यात्मिक और बौद्धिक संपर्क भी स्थापित किए (Gupta, 2021)।

मुग़ल साम्राज्य के संस्थापक बाबर का जन्म फ़रग़ना घाटी में हुआ था, जो वर्तमान उज़्बेकिस्तान का हिस्सा है। बाबर की आत्मकथा और उस समय के अन्य ऐतिहासिक स्रोत भारत–मध्य एशिया सांस्कृतिक और राजनीतिक संपर्क की गहराई को दर्शाते हैं। मुग़ल शासन के दौरान मध्य एशियाई कला, वास्तुकला, भाषा और खान–पान के कई तत्व भारतीय समाज में समाहित हो गए। औपनिवेशिक काल और बाद में सोवियत संघ के तहत मध्य एशिया के आने से यह परंपरागत संपर्क कमजोर हुआ, लेकिन सांस्कृतिक स्मृति और सभ्यतागत जुड़ाव दोनों समाजों में बना रहा। स्वतंत्रता–उत्तर काल में भारत ने इस ऐतिहासिक विरासत को आधुनिक कूटनीति के साथ पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है।

3.2 स्वतंत्रोत्तर काल और कूटनीतिक संबंधों की स्थापना

सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 में उज़्बेकिस्तान ने स्वतंत्रता प्राप्त की। भारत ने शीघ्रता से उज़्बेकिस्तान को मान्यता दी और 1992 में दोनों देशों के बीच औपचारिक कूटनीतिक संबंध स्थापित हुए। प्रारंभिक वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध मुख्यतः राजनीतिक संपर्क, सीमित व्यापार, विज्ञान–प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग तक सीमित रहे (Ilhomovich, 2025)। भारत ने ताशकंद में अपना दूतावास स्थापित किया, जबकि उज़्बेकिस्तान ने नई दिल्ली में अपना मिशन खोला। दोनों देशों के बीच उच्चस्तरीय यात्राएँ होने लगीं, जिनमें मित्रता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के पारस्परिक सम्मान पर बल दिया गया। समय के साथ–साथ आतंकवाद–रोधी सहयोग, सुरक्षा संवाद, ऊर्जा–सुरक्षा, विज्ञान–प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल्स और आईटी जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग के नए आयाम जुड़ते गए, जिसने संबंधों को एक व्यापक रूप दिया।

3.3 2011 की रणनीतिक साझेदारी और उसके बाद का विकास

साल 2011 भारत–उज़्बेकिस्तान संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था, जब दोनों देशों ने अपने रिश्तों को औपचारिक रूप से "रणनीतिक साझेदारी" का दर्जा प्रदान किया। इस घोषणा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक दीर्घकालिक, संरचित और बहु–आयामी ढाँचा दिया। रणनीतिक साझेदारी के अंतर्गत नियमित शिखर–वार्ताएँ, विदेश मंत्रिस्तरीय संवाद, रक्षा–सहयोग समितियाँ, संयुक्त आर्थिक आयोग और विभिन्न क्षेत्र–विशेष कार्य–समूह गठित किए गए। दोनों देश शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य होने के नाते क्षेत्रीय आतंकवाद–रोधी संरचना, अफगानिस्तान की स्थिरता, और क्षेत्रीय संपर्क पर भी मिलकर विचार करते हैं।

2011 के बाद के दशक में उच्चस्तरीय यात्राओं की आवृत्ति बढ़ी है (Jahanzaib, 2024)। इन यात्राओं के दौरान रक्षा–सुरक्षा, व्यापार–निवेश, संपर्क, ऊर्जा, शिक्षा, संस्कृति, सूचना–प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य, कृषि–प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में समझौते हुए हैं, जिन्होंने संबंधों को नई गहराई प्रदान की है।

4. वर्तमान रणनीतिक सहयोग: प्रमुख आयाम

4.1 राजनीतिक और कूटनीतिक संवाद

भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंध विश्वास, परस्पर सम्मान और साझा हितों पर आधारित हैं। दोनों देशों के नेतृत्व स्तर पर नियमित संवाद होता है। शिखर–वार्ताओं, मंत्रिस्तरीय बैठकों और अधिकारियों के स्तर पर होने वाली वार्ताओं ने एक संस्थागत कूटनीतिक ढाँचा तैयार किया है, जिसके कारण नीति–निर्माण में निरंतरता बनी रहती है। दोनों देश संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, अंतरराष्ट्रीय कानून के सम्मान, आतंकवाद के प्रति शून्य–सहनशीलता, और नियम–आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जैसे बुनियादी सिद्धांतों पर सहमत हैं। उज़्बेकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर कई अवसरों पर भारत की पहलों का समर्थन किया है, जबकि भारत ने उज़्बेकिस्तान के आंतरिक सुधार–कार्यक्रम और क्षेत्रीय कूटनीति का स्वागत किया है (Jindal, 2024)।

उज़्बेकिस्तान की विदेश नीति में क्षेत्रीय स्थिरता, आर्थिक आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी को जो महत्त्व दिया गया है, वह भारत की "पड़ोस और विस्तारित पड़ोस"–केंद्रित नीति के साथ तालमेल बैठाता है। इस प्रकार, राजनीतिक स्तर पर दोनों देशों के बीच एक साझा वैचारिक आधार मौजूद है जो रणनीतिक सहयोग को सहज बनाता है।

4.2 रक्षा और सुरक्षा सहयोग

भारत–उज़्बेकिस्तान रक्षा–सहयोग समय के साथ धीरे–धीरे परिपक्व हुआ है। दोनों देशों के बीच रक्षा–समझौते, प्रशिक्षण कार्यक्रम, संयुक्त सैन्य अभ्यास और उच्चस्तरीय रक्षा–प्रतिनिधिमंडलों की यात्राएँ नियमित होती रही हैं। आतंकवाद, कट्टरपंथ और सीमा–पार संगठित अपराध के विरुद्ध सहयोग सुरक्षा–संवाद का केंद्रीय तत्व है।

अफगानिस्तान की स्थिति दोनों देशों के लिए साझा चिंता का विषय है। उग्रवाद, चरमपंथ, हथियारों की अवैध तस्करी, ड्रग–ट्रैफ़िकिंग और शरणार्थी संकट जैसी समस्याएँ क्षेत्रीय स्थिरता को प्रभावित करती हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान, दोनों, एक स्थिर, समावेशी और आतंकवाद–मुक्त अफगानिस्तान के पक्षधर हैं (Kolkanov, 2025)। इस संदर्भ में सुरक्षा–समन्वय, खुफ़िया–सूचना साझा करना और क्षेत्रीय मंचों पर नीति–समन्वय का विशेष महत्त्व है। इसके अतिरिक्त, दोनों देश साइबर–सुरक्षा, महत्वपूर्ण अवसंरचना की सुरक्षा, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर अतिवादी विचारधाराओं की रोकथाम, और सीमा–पार आपराधिक नेटवर्क के विरुद्ध सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं।

4.3 आर्थिक और व्यापारिक संबंध

आर्थिक और व्यापारिक क्षेत्र में भारत–उज़्बेकिस्तान संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है, लेकिन यह सहयोग अभी भी अपनी पूरी संभावनाओं से कम स्तर पर है। पिछले कुछ वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार का स्तर बढ़ा है, फिर भी दोनों पक्ष इसे वास्तविक क्षमता से काफी नीचे मानते हैं। भारत से उज़्बेकिस्तान को औषधीय उत्पाद, मशीनरी, ऑटो–पुर्जे, आईटी उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कृषि–उपकरण, चाय–कॉफ़ी, मसाले और विभिन्न प्रकार की सेवाएँ निर्यात की जाती हैं (Kumari, 2024)। दूसरी ओर उज़्बेकिस्तान से भारत को फलों–सब्ज़ियों, सूखे मेवों, कपास, रेशम, कुछ खनिज उत्पादों और रसायनों का निर्यात होता है।

भारत की सरकारी वित्तीय संस्थाओं ने उज़्बेकिस्तान में अवसंरचना विकास, ऊर्जा और उद्योग–प्रसंस्करण से संबंधित परियोजनाओं के लिए रियायती ऋण और लाइन–ऑफ़–क्रेडिट उपलब्ध कराई हैं। इसके माध्यम से सड़क, बिजली, जल–आपूर्ति और अन्य क्षेत्रों में परियोजनाएँ चल रही हैं। फिर भी व्यापार–वर्धन की राह में कई बाधाएँ हैं। प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क का अभाव, लंबी आपूर्ति–श्रृंखला, ऊँची लॉजिस्टिक लागत, जटिल कस्टम प्रक्रियाएँ, वित्तीय लेनदेन में अनिश्चितता और व्यापार–विविधीकरण की कमी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

4.4 संपर्क एवं परिवहन कॉरिडोर

संपर्क–कूटनीति भारत–उज़्बेकिस्तान रणनीतिक सहयोग का केंद्रीय आयाम है। दोनों देशों को जोड़ने वाला कोई सीधा समुद्री मार्ग नहीं है, इसलिए स्थलीय और समुद्री–स्थलीय संयुक्त कॉरिडोरों का विकास अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत, ईरान और रूस के सहयोग से विकसित हो रहा अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन कॉरिडोर तथा ईरान के चाबहार बंदरगाह पर भारत की भागीदारी मध्य एशिया तक पहुँचने का स्वाभाविक विकल्प है। यदि इन मार्गों का उपयोग व्यापक रूप से हो सके तो भारत–

उज़्बेकिस्तान के बीच माल परिवहन की लागत और समय, दोनों में उल्लेखनीय कमी आ सकती है (Lahiry, 2024)।

हाल के वर्षों में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच चाबहार के माध्यम से पायलट कार्गो भेजने, ट्रांज़िट समझौतों और त्रिपक्षीय संवादों के माध्यम से इस दिशा में व्यावहारिक कदम उठाए गए हैं। उधर उज़्बेकिस्तान भी स्वयं को विभिन्न संपर्क–कॉरिडोरों से जोड़ रहा है। चीन–किर्गिस्तान–उज़्बेकिस्तान रेल–मार्ग, कज़ाखस्तान–रूस–यूरोप कॉरिडोर, तुर्कमेनिस्तान–ईरान–ओमान मार्ग, और संभावित ट्रांस–अफगान कॉरिडोर उसके संपर्क–दृष्टिकोण के संकेतक हैं। भारत और उज़्बेकिस्तान इन अलग–अलग पहलों को जोड़कर एक लचीला, बहु–मार्गीय नेटवर्क विकसित कर सकते हैं।

4.5 ऊर्जा, हरित–ऊर्जा और संसाधन–सुरक्षा

ऊर्जा–सुरक्षा दोनों देशों के लिए एक प्रमुख चिंता और अवसर का क्षेत्र है। उज़्बेकिस्तान प्राकृतिक गैस, यूरेनियम, सोना और अन्य खनिजों से समृद्ध है, जबकि भारत एक तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था होने के कारण ऊर्जा–आयात पर अत्यधिक निर्भर है। अभी तक द्विपक्षीय ऊर्जा–सहयोग सीमित स्तर पर है, किंतु दीर्घकालिक संभावनाएँ काफी विस्तृत हैं (Mansoor and Pandey, 2024)।

प्राकृतिक गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, बिजली–संप्रेषण और ऊर्जा–कुशल तकनीकों में दोनों देशों के बीच निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाएँ हैं। भारत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ऊर्जा–कुशल तकनीकों के क्षेत्र में अनुभव रखता है, जबकि उज़्बेकिस्तान हरित–ऊर्जा निवेश की संभावनाएँ तलाश रहा है। यदि संपर्क–कॉरिडोर व्यवहारिक रूप से सुदृढ़ होते हैं, तो भविष्य में मध्य एशिया से भारत तक ऊर्जा–आपूर्ति की नई योजनाएँ भी संभव हो सकती हैं, जो भारत की ऊर्जा–विविधीकरण नीति के अनुरूप होंगी।

4.6 शिक्षा, संस्कृति और लोगों–से–लोगों के संबंध

शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भारत–उज़्बेकिस्तान सहयोग लगातार बढ़ रहा है। उज़्बेक छात्रों के लिए भारतीय विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के अवसर, छात्रवृत्तियाँ और तकनीकी–प्रशिक्षण कार्यक्रम उपलब्ध हैं। दूसरी ओर भारतीय छात्रों और शोधार्थियों के लिए मध्य एशियाई इतिहास, सूफी परंपरा, इस्लामी अध्ययन और क्षेत्रीय अध्ययन के संदर्भ में उज़्बेकिस्तान आकर्षक गंतव्य बन रहा है। भारत की सॉफ्ट–पावर – जैसे योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड सिनेमा, संगीत और नृत्य – उज़्बेकिस्तान में भी लोकप्रिय हो रहे हैं। सांस्कृतिक महोत्सवों, फ़िल्म–सप्ताह, संगीत–कार्यक्रमों, योग–दिवस और भाषा–केंद्रों के माध्यम से दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक पुल मज़बूत हो रहे हैं (Movkebayeva, 2021)।

सूफी संतों की साझा विरासत, सूफी मज़ारों और ऐतिहासिक–धार्मिक स्थलों पर केंद्रित आध्यात्मिक पर्यटन की संभावनाएँ भी काफी हैं। इससे न केवल पर्यटन–आय बढ़ेगी, बल्कि समाज–समाज के स्तर पर आपसी निकटता और विश्वास भी प्रगाढ़ होगा।

5. अवसर: नई विश्व व्यवस्था में साझेदारी के विस्तार की दिशा

5.1 बहुध्रुवीयता और सामरिक स्वायत्तता के साझा हित

भारत और उज़्बेकिस्तान दोनों बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी–अपनी सामरिक स्वायत्तता को सुरक्षित और सुदृढ़ करना चाहते हैं। भारत नहीं चाहता कि एशिया में किसी एक शक्ति का पूर्ण वर्चस्व हो, वहीं उज़्बेकिस्तान किसी एक शक्तिकेंद्र – चाहे वह रूस हो या चीन – पर अत्यधिक निर्भरता से बचना चाहता है। यह साझा दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच रणनीतिक समझ को स्वाभाविक रूप से मज़बूत करता है। भारत–उज़्बेकिस्तान सहयोग केवल द्विपक्षीय लाभ तक सीमित न रहकर एक व्यापक वैचारिक परियोजना का हिस्सा बनता है, जिसमें संतुलित, बहुध्रुवीय और समावेशी विश्व व्यवस्था की कल्पना निहित है।

5.2 संपर्क–कॉरिडोर और क्षेत्रीय एकीकरण के अवसर

संपर्क–कॉरिडोरों के माध्यम से क्षेत्रीय एकीकरण के व्यापक अवसर मौजूद हैं। यदि चाबहार बंदरगाह और अंतरराष्ट्रीय उत्तर–दक्षिण परिवहन कॉरिडोर को व्यापक रूप से उपयोग में लाया जा सके, तो भारत–उज़्बेकिस्तान के बीच व्यापारिक सहयोग में गुणात्मक वृद्धि संभव है (Muratbekova, 2024)।

यूरोप–मध्य एशिया, रूस–मध्य एशिया, चीन–मध्य एशिया और दक्षिण एशिया–मध्य एशिया के विभिन्न कॉरिडोरों को जोड़कर एक जाल–सदृश नेटवर्क विकसित किया जा सकता है, जिसमें भारत–उज़्बेकिस्तान प्रमुख साझेदार होंगे। इससे दोनों देशों को बाज़ार–विविधीकरण, आपूर्ति–श्रृंखला सुरक्षा और निवेश–वर्धन के नए अवसर मिलेंगे।

5.3 रक्षा, आतंकवाद–रोधी और साइबर–सुरक्षा सहयोग

अफगानिस्तान की स्थिति, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, कट्टरपंथ और अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी संगठनों की सक्रियता ने क्षेत्रीय सुरक्षा को जटिल बना दिया है। इस परिप्रेक्ष्य में भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच आतंकवाद–रोधी सहयोग, संयुक्त अभ्यास, खुफ़िया सूचना–साझाकरण, सीमा–पार अपराधों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई तथा साइबर–सुरक्षा सहयोग के विशाल अवसर हैं। दोनों देशों के सुरक्षा–तंत्र के बीच नियमित संवाद, संस्थागत तंत्र और क्षमता–निर्माण कार्यक्रम न केवल द्विपक्षीय सुरक्षा को मज़बूत कर सकते हैं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता में भी योगदान दे सकते हैं।

5.4 आर्थिक–व्यापारिक विविधीकरण और उद्योग–विशेष साझेदारी

द्विपक्षीय व्यापार को उच्च स्तर तक ले जाने के लिए पारंपरिक व्यापार–ढांचे से आगे बढ़ना आवश्यक है (Museyibzada, 2023)।

ज्ञान–आधारित और उच्च–मूल्य क्षेत्रों – जैसे फार्मास्युटिकल्स, सूचना–प्रौद्योगिकी, कृषि–प्रसंस्करण, वस्त्र–उद्योग, स्वास्थ्य–पर्यटन, कौशल–विकास, स्टार्ट–अप और डिजिटल सेवाएँ – में सहयोग की अत्यधिक संभावनाएँ हैं। भारत की औषधि–उद्योग, आईटी सेवा, स्टार्ट–अप और शिक्षा–क्षेत्र में क्षमता, तथा उज़्बेकिस्तान की युवा जनसंख्या, सुधार–उन्मुख नीतियाँ और भू–स्थानिक स्थिति दोनों को परस्पर पूरक साझेदार बनाती हैं। संयुक्त उद्यम, टेक–पार्क, विशेष आर्थिक क्षेत्र और कौशल–केंद्र स्थापित कर इस पूरकता को व्यवहार में ढाला जा सकता है।

5.5 शिक्षा, संस्कृति और मानवीय संपर्क

शिक्षा–क्षेत्र में संयुक्त शोध–परियोजनाएँ, द्वैध–डिग्री कार्यक्रम, ऑनलाइन–संयुक्त पाठ्यक्रम, और भाषा–केंद्रों का विस्तार दीर्घकालिक साझेदारी का मजबूत आधार बन सकता है। भारत के विश्वविद्यालयों में मध्य एशिया अध्ययन और उज़्बेकिस्तान के विश्वविद्यालयों में भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन देकर दोनों समाजों के बीच बौद्धिक समझ बढ़ाई जा सकती है। सांस्कृतिक स्तर पर फ़िल्म–उत्सव, साहित्यिक संवाद, संगीत–महोत्सव, योग–कार्यक्रम और सूफी सम्मेलन जैसे आयोजन सॉफ्ट–पावर को बढ़ाने के साथ–साथ, लोगों–से–लोगों के संपर्क को भी सशक्त कर सकते हैं।

6. चुनौतियाँ: संरचनात्मक बाधाएँ और भू–राजनीतिक जोखिम

6.1 लॉजिस्टिक और अवसंरचनात्मक चुनौतियाँ

भारत–उज़्बेकिस्तान आर्थिक और संपर्क–सहयोग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है प्रत्यक्ष समुद्री संपर्क का अभाव और लंबी, बहु–स्तरीय स्थलीय मार्गों पर निर्भरता। वर्तमान मार्गों से माल परिवहन समय–साध्य और महँगा है, जिससे द्विपक्षीय व्यापार की प्रतिस्पर्धात्मकता प्रभावित होती है (Movkebayeva, 2021)। कस्टम प्रक्रियाओं की जटिलता, सीमा–पार समन्वय की कमी, परिवहन–बीमा से जुड़ी अनिश्चितताएँ और वित्तीय लेनदेन की कठिनाइयाँ भी व्यापार–खर्च को बढ़ाती हैं। जब तक इन संरचनात्मक बाधाओं को संबोधित नहीं किया जाता, तब तक रणनीतिक साझेदारी की आर्थिक नींव अपेक्षित स्तर तक मज़बूत नहीं हो पाएगी।

6.2 ईरान, प्रतिबंध और चाबहार से जुड़ी अनिश्चितताएँ

चाबहार बंदरगाह भारत और उज़्बेकिस्तान सहित पूरे मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए समुद्री संपर्क का एक महत्त्वपूर्ण द्वार बन सकता है। परंतु ईरान पर लगाए गए प्रतिबंध, पश्चिम–ईरान संबंधों में तनाव, और संभावित द्वितीयक प्रतिबंधों की आशंका जैसी कारक इस परियोजना से जुड़ी अनिश्चितताएँ पैदा करते हैं। इन कारणों से कई निजी कंपनियाँ और वित्तीय संस्थान चाबहार से संबंधित निवेश–निर्णयों में सावधानी बरतती हैं, जिससे परियोजना के तेज़ी से विकास में बाधा आती है। भारत और उज़्बेकिस्तान, दोनों, इस मार्ग के दीर्घकालिक रणनीतिक लाभों को समझते हैं, लेकिन उन्हें तृतीय पक्ष के दबावों और भू–राजनीतिक जोखिमों को ध्यान में रखते हुए संतुलित रणनीति अपनानी पड़ती है।

6.3 अफगानिस्तान की अस्थिरता

अफगानिस्तान भौगोलिक रूप से भारत और उज़्बेकिस्तान के बीच स्वाभाविक संपर्क–पुल हो सकता है। संभावित ट्रांस–अफगान रेल या सड़क–कॉरिडोर दोनों देशों के बीच दूरी और लागत को काफी हद तक कम कर सकते हैं। लेकिन अफगानिस्तान की राजनीतिक और सुरक्षा स्थिति अत्यंत अनिश्चित है (Muratbekova, 2024)। अंतरराष्ट्रीय मान्यता का संकट, चरमपंथी संगठनों की सक्रियता, मानवाधिकार और समावेशी शासन के प्रश्न, और आर्थिक अस्थिरता जैसे कारक किसी भी बड़े अवसंरचनात्मक निवेश को जोखिमपूर्ण बनाते हैं। यदि स्थिति बिगड़ती है, तो भारत–उज़्बेकिस्तान के लिए अफगान मार्ग अव्यवहारिक हो सकता है, जिसके कारण उन्हें अपेक्षाकृत लंबी लेकिन अपेक्षाकृत सुरक्षित वैकल्पिक मार्गों पर निर्भर रहना होगा।

6.4 क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और चीन–कारक

मध्य एशिया चीन की बेल्ट एंड रोड पहल का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। उज़्बेकिस्तान सहित अधिकांश देश चीनी निवेश, ऋण और अवसंरचना परियोजनाओं में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। इससे संपर्क–अवसंरचना तो विकसित हुई है, लेकिन ऋण–निर्भरता, व्यापार–असंतुलन और राजनीतिक प्रभाव के प्रश्न भी उठे हैं। भारत बेल्ट एंड रोड परियोजना का औपचारिक हिस्सा नहीं है और एक वैकल्पिक, पारदर्शी और सहयोग–प्रधान संपर्क–दृष्टि प्रस्तुत करना चाहता है। इस संदर्भ में कभी–कभी क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा की आशंका भी उत्पन्न होती है कि क्या भारत–उज़्बेकिस्तान सहयोग चीन–केंद्रित परियोजनाओं के साथ प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति में होगा या पूरक रूप ले सकेगा। भारत के लिए चुनौती यह है कि वह अपने प्रस्तावों को वित्तीय रूप से स्थिर, स्थानीय क्षमता–निर्माण पर आधारित और पारदर्शी बनाकर आकर्षक बनाए, ताकि उज़्बेकिस्तान को चीन और रूस के साथ संतुलित विकल्प मिल सके।

6.5 घरेलू सुधार, संस्थागत क्षमता और नीतिगत निरंतरता

उज़्बेकिस्तान व्यापक आर्थिक, प्रशासनिक, कानूनी और सामाजिक सुधारों के दौर से गुजर रहा है। सुधार–प्रक्रिया स्वाभाविक रूप से समय–साध्य है और उसके साथ कुछ अनिश्चितताएँ भी जुड़ी रहती हैं (Museyibzada, 2023)। निवेशकों को नियामक–स्थिरता, पारदर्शिता और न्यायिक निष्पक्षता की स्पष्ट गारंटी की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार भारत में भी

संघीय ढाँचा, विभिन्न स्तरों की नौकरशाही, भूमि–अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति और अन्य नियामक प्रक्रियाएँ कभी–कभी दीर्घकालिक परियोजनाओं के क्रियान्वयन को जटिल बना देती हैं। इन चुनौतियों से निपटने के लिए दोनों देशों को संस्थागत क्षमता–निर्माण, नीति–निरंतरता, सिंगल–विंडो सिस्टम, समय–बद्ध अनुमोदन और नियामक स्पष्टता पर विशेष ध्यान देना होगा।

7. भविष्य की संभावनाएँ और नीतिगत सुझाव

7.1 रणनीतिक साझेदारी 2.0 की दिशा

नई विश्व व्यवस्था में भारत–उज़्बेकिस्तान को अपनी साझेदारी को अगले चरण में ले जाने के लिए एक दीर्घकालिक दृष्टि–दस्तावेज़ की आवश्यकता है (Rangsimaporn, 2022)। "रणनीतिक साझेदारी 2.0" के रूप में इसे समझा जा सकता है, जिसमें केवल सरकारी–स्तर के समझौतों से आगे बढ़कर निजी क्षेत्र, राज्य–स्तरीय सरकारों, विश्वविद्यालयों, थिंक–टैंकों और नागरिक समाज की भूमिका को भी स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। दोनों देश मिलकर एक "भारत–उज़्बेकिस्तान दृष्टि–दस्तावेज़ 2040" तैयार कर सकते हैं, जिसमें राजनीति, सुरक्षा, संपर्क, व्यापार, ऊर्जा, डिजिटल सहयोग, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में ठोस लक्ष्य, माइलस्टोन और समीक्षा–तंत्र निर्धारित हों। इससे सहयोग न केवल विस्तृत होगा बल्कि निरंतरता और जवाबदेही भी सुनिश्चित हो सकेगी।

7.2 संपर्क–कूटनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता

रणनीतिक सहयोग की स्थायी आधारशिला के रूप में संपर्क–कूटनीति को प्राथमिकता देना आवश्यक है। चाबहार–INSTC मार्ग, पायलट कंटेनर–शिपमेंट, सीमा–पार कस्टम सहयोग, ट्रांज़िट समझौते और डिजिटल कनेक्टिविटी को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। अल्पकालीन दृष्टि में चाबहार–आधारित समुद्री–स्थलीय मार्ग को अधिक व्यावसायिक रूप से आकर्षक बनाने, लॉजिस्टिक लागत घटाने, कस्टम–समन्वय बढ़ाने और निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने पर जोर देना चाहिए। दीर्घकाल में, अफगानिस्तान की स्थिति के अनुकूल होते ही ट्रांस–अफगान रेल या सड़क–कॉरिडोर की संभावनाओं की पुनः समीक्षा की जा सकती है (Rasool and Zaheer, 2024)।

इसके साथ–साथ डिजिटल कनेक्टिविटी, फाइबर–ऑप्टिक नेटवर्क, डेटा–सेंटर सहयोग और ई–कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्मों को भी संपर्क–कूटनीति के हिस्से के रूप में विकसित किया जा सकता है, जिससे ज्ञान–आधारित अर्थव्यवस्था और सेवाक्षेत्र को भी लाभ होगा।

7.3 व्यापार–विविधीकरण और उद्योग–विशेष साझेदारी

द्विपक्षीय व्यापार को गुणात्मक रूप से बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों को अपनी–अपनी ताकतों की पहचान कर उद्योग–विशेष साझेदारी पर जोर देना चाहिए। फार्मास्युटिकल्स में संयुक्त उत्पादन इकाइयाँ, जेनेरिक दवाओं के लिए अनुसंधान एवं विकास केंद्र, आईटी और बीपीओ केंद्र, कृषि–प्रसंस्करण पार्क, और वस्त्र–डिज़ाइन तथा रेडीमेड वस्त्रों के संयुक्त ब्रांड ऐसे उदाहरण हैं, जहाँ अपेक्षाकृत कम पूँजी निवेश से भी तेज़ परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं (Ray and Upadhyay, 2024)।

स्वास्थ्य–पर्यटन और शिक्षा–पर्यटन भी महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। भारतीय अस्पतालों और चिकित्सा–संस्थानों की सेवाएँ उज़्बेक नागरिकों के लिए आकर्षक हो सकती हैं, जबकि उज़्बेकिस्तान के ऐतिहासिक–धार्मिक स्थल भारतीय पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र हैं।

7.4 शिक्षा–ज्ञान साझेदारी और मानव पूँजी विकास

दीर्घकालिक सहयोग का सबसे सुदृढ़ आधार मानव–पूँजी का विकास है। भारत और उज़्बेकिस्तान दोनों युवाओं की बड़ी आबादी वाले देश हैं। शिक्षा–ज्ञान साझेदारी, कौशल–विकास, अनुसंधान सहयोग और स्टार्ट–अप इकोसिस्टम में सहकार्य से भविष्य की पीढ़ियों के बीच भी घनिष्ठता विकसित होगी।

दोनों देशों के विश्वविद्यालयों के बीच द्वैध–डिग्री कार्यक्रम, छात्र–अदला–बदली, संयुक्त शोध–परियोजनाएँ और ऑनलाइन–संयुक्त पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा सकते हैं। भारत के "स्टडी इन इंडिया" जैसी पहलों में उज़्बेक छात्रों के लिए विशेष छात्रवृत्तियाँ और उज़्बेक विश्वविद्यालयों में हिंदी, योग, भारतीय संस्कृति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों पर केंद्रित केंद्रों की स्थापना इस दिशा में सार्थक कदम होंगे।

7.5 बहुपक्षीय मंचों पर समन्वित कूटनीति

भारत और उज़्बेकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन, संयुक्त राष्ट्र, भारत–मध्य एशिया संवाद, जलवायु–सम्मेलनों, डिजिटल–शासन मंचों और अन्य क्षेत्रीय–वैश्विक संस्थाओं में सक्रिय हैं (Uljevic, 2024)। इन मंचों पर समन्वित कूटनीति के माध्यम से दोनों देश बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी सामूहिक आवाज़ को मजबूत बना सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय कानून, आतंकवाद–रोधी मानकों, डिजिटल–गवर्नेंस, जलवायु–न्याय, सतत विकास लक्ष्यों और आपूर्ति–श्रृंखला सुरक्षा जैसे विषयों पर साझा या पूरक प्रस्तावों के माध्यम से भारत और उज़्बेकिस्तान "नॉर्म–निर्माता" के रूप में भी उभर सकते हैं। इससे न केवल दोनों देशों की भूमिका मज़बूत होगी, बल्कि नई विश्व व्यवस्था को अधिक समावेशी और संतुलित बनाने में भी सहायता मिलेगी।

8. निष्कर्ष

नई विश्व व्यवस्था में भारत–उज़्बेकिस्तान रणनीतिक सहयोग बहुध्रुवीयता, सामरिक स्वायत्तता और संतुलित क्षेत्रीय व्यवस्था की व्यापक परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐतिहासिक–

सांस्कृतिक जुड़ाव, साझा हितों और विकसित हो रहे संपर्क–कॉरिडोरों ने दोनों देशों के संबंधों को केवल पारंपरिक द्विपक्षीय सीमाओं से बाहर निकालकर बहु–आयामी रणनीतिक साझेदारी में बदल दिया है। 2011 में घोषित रणनीतिक साझेदारी के बाद से राजनीतिक–कूटनीतिक संवाद, रक्षा–सुरक्षा सहयोग, व्यापार–निवेश, संपर्क–कूटनीति, शिक्षा–संस्कृति और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वय ने निरंतर प्रगति की है (Yuldasheva, 2022)। यह प्रगति इस तथ्य को दर्शाती है कि भारत और उज़्बेकिस्तान दोनों बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अपनी भूमिका को सक्रिय रूप से परिभाषित करना चाहते हैं और इसके लिए वे एक–दूसरे को विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखते हैं।

इसके बावजूद यह भी स्पष्ट है कि द्विपक्षीय संबंध अभी अपनी समस्त संभावनाओं तक नहीं पहुँच पाए हैं। लॉजिस्टिक और अवसंरचनात्मक बाधाएँ, अफगानिस्तान की अस्थिरता, ईरान से जुड़े भू–राजनीतिक जोखिम, क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा और घरेलू संस्थागत चुनौतियाँ इस सहयोग को सीमित करती हैं। इन अवरोधों को दूर करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि, नीतिगत स्थिरता, संस्थागत क्षमता–निर्माण और बहु–स्तरीय भागीदारी की आवश्यकता है। यदि भारत और उज़्बेकिस्तान संपर्क–कूटनीति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए व्यापार–विविधीकरण, ज्ञान–साझेदारी, हरित–ऊर्जा सहयोग और बहुपक्षीय मंचों पर समन्वित कूटनीति को व्यवस्थित ढंग से आगे बढ़ाते हैं, तो वे न केवल अपने द्विपक्षीय हितों को सुदृढ़ करेंगे, बल्कि बहुध्रुवीय, समावेशी और नियम–आधारित नई विश्व व्यवस्था के निर्माण में भी संयुक्त रूप से महत्त्वपूर्ण योगदान दे पाएँगे। इस दृष्टि से भारत–उज़्बेकिस्तान रणनीतिक सहयोग नई विश्व व्यवस्था की जटिलताओं के बीच अवसर, चुनौतियाँ और संभावनाओं के एक जीवंत उदाहरण के रूप में उभरने की क्षमता रखता है।

संदर्भ

1. Baghdasaryan, S., 2024. नए विश्व व्यवस्था और ग्रेटर मिडिल ईस्ट व इंडो-पैसिफिक क्षेत्रों की रणनीतिक सुरक्षा स्थिति. **Armenological Issues**, 29(2), pp.112–130.
2. Barari, K. and Mozaffari Falarti, M., 2023. मध्य एशियाई गणराज्य: नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत की परिवर्तित विदेश नीति. **Journal of Iran and Central Eurasia Studies**, 6(1), pp.49–67.
3. Bukhari, S.R.H., 2025. यूरेशिया का उभार: चीन–रूस–उत्तर कोरिया अक्ष, एससीओ का रूपांतरण और नए ब्लॉक विश्व-व्यवस्था में पाकिस्तान के रणनीतिक विकल्प. **Journal of Regional Studies Review**, 9(1), pp.101–120.
4. Gupta, P.K., 2021. भारत और मध्य एशिया के बीच रक्षा सहयोग. **Indian Foreign Affairs Journal**, 16(3), pp.215–231.
5. Ilhomovich, A.A., 2025. उज़्बेकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय संबंध. **Obrazovanie i Nauka v XXI Veke**, 15(1), pp.34–48.
6. Jahanzaib, M., 2024. परिवर्तित विश्व में मध्य एशियाई गणराज्य–पाकिस्तान संबंध: एक उदारवादी (neoliberal) दृष्टिकोण. **Journal of Politics and International Studies**, 20(2), pp.132–149.
7. Jindal, N., 2024. नई विश्व-व्यवस्था में चीन और यूरेशिया. **Politicosse Review**, 4(2), pp.88–102.
8. Kolkanov, N., 2025. उज़्बेकिस्तान की विदेश नीति की प्राथमिक दिशाएँ. **International Journal of Artificial Intelligence**, 7(1), pp.45–58.
9. Kumari, K., 2024. उज़्बेकिस्तान: क्षेत्रीय और अंतरक्षेत्रीय सहयोग का विस्तार. **Himalayan & Central Asian Studies**, 28(2), pp.51–66.
10. Lahiry, S., 2024. भारत और समकालीन विश्व-व्यवस्था: समीक्षा और संभावनाएँ. **The Review of International Affairs**, 73(1), pp.84–99.
11. Mansoor, W. and Pandey, N., 2024. भारत की विदेश नीति: UPA II और NDA II (2009–2019) का दस्तावेजीय विश्लेषण. **Journal of Political Studies**, 18(2), pp.141–160.
12. Movkebayeva, G.A., 2021. भारत और मध्य एशिया के बीच सहयोग तथा क्षेत्र के लिए इसकी महत्ता. **Bulletin of the Karaganda University: History, Philosophy Series**, 103(1), pp.71–83.
13. Muratbekova, A.M., 2024. कज़ाख़स्तान में भारत की विदेश नीति: सहयोग की संभावनाओं का विश्लेषण. **International Relations & Diplomacy**, 11(4), pp.203–217.
14. Museyibzada, J., 2023. उज़्बेकिस्तान की विदेश नीति में परिवर्तन: अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से प्रतिष्ठा और सहयोग निर्माण में सक्रिय भागीदारी. **Farg'ona Davlat Universiteti Ilmiy Jurnali**, 11(2), pp.77–89.
15. Museyibzada, J., 2024. अंतरराष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से उज़्बेकिस्तान के आर्थिक सहयोग में सुधार. **Farg'ona Davlat Universiteti Ilmiy Jurnali**, 12(3), pp.57–68.
16. Rangsimaporn, P., 2022. उज़्बेकिस्तान और दक्षिण-पूर्व एशिया: संबंध मज़बूत करने की संभावनाएँ. **Silk Road: A Journal of Eurasia Development**, 10(1), pp.23–41.
17. Rasool, M. and Zaheer, M.A., 2024. क्षेत्रीय गतिशीलता और आतंकवाद-रोधी सहयोग: मध्य एशिया में पाकिस्तान–रूस सहभागिता. **International Relations – International Journal**, 6(3), pp.55–72.
18. Ray, A.S. and Upadhyay, V., 2024. एकध्रुवीय विश्व-व्यवस्था की चुनौतियाँ: दो मौजूदा युद्ध और ग्लोबल साउथ का सुदृढ़ीकरण. **SSRN Working Paper Series**, Paper No. 5050420, pp.1–32.

19. Uljevic, S., 2024. मध्य एशिया में भारत की भागीदारी और चीन के साथ प्रतिस्पर्धा: बहुध्रुवीय विश्व-व्यवस्था 2.0. In: **Handbook of Chinese and Eurasian International Relations**. London: Taylor & Francis, pp.221–239.
20. Yuldasheva, G.I., 2022. मध्य एशिया में नई अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्रवृत्तियाँ. In: **International Congress 2022: Future Vision in Central Asia**, Ankara: Arel University Press, pp.96–108.